आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
सोमवार 11.08.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी के हर्षिल–धराली आपदा स्थल पर खोज और बचाव कार्य तेज किया। हर्षिल क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील से पानी की निकासी का कार्य शुरू।
- पौड़ी जिले में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का अध्ययन के लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग के तीन अधिकारियों की एक टीम गठन किया गया।
- प्रदेश के अधिकांश जिलों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी।
- मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, उधमसिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

हर्षिल राहत और बचाव अभियान

उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के एक सप्ताह बाद भी खोजबीन तथा राहत व बचाव कार्य जारी हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने मौसम की चुनौतियों के बीच अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी है। खराब मौसम के बावजूद राहतकर्मी जमीनी स्तर पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं।

हर्षिल क्षेत्र में बनी कृत्रिम झील से पानी की निकासी का कार्य शुरू हो गया है, जिससे निचले इलाकों में भागीरथी नदी का जलस्तर बढने की सम्भावना है। साथ ही जल निकासी के लिए सिंचाई विभाग मैनुअल तरीके से रास्ता बनाने की तैयारी में है। इस कार्य के लिए विभाग के अधिकारी और श्रमिकों को हेलिकॉप्टर के जरिए हर्षिल भेजा जाएगा, जहां उन्हें स्थायी रूप से कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। जल निकासी कार्य में सहयोग के लिए यूजेवीएनएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है।

हालांकि, उत्तरकाशी में आज हो रही बारिश के कारण धराली क्षेत्र में हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। मौसम खराब होने के कारण हेली ऑपरेशन पर फिलहाल रोक लगी हुई है।

बयान

धराली में बचाव और राहत अभियान को लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि आपदा के बाद लगभग बारह सौ से तेरह सौ लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीमें दिन–रात काम कर रही हैं और सड़क संपर्क बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित को साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री स्वयं राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

भू वैज्ञानिकों सदस्यीय टीम का गठन

पौड़ी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में अवरूद्ध सड़कों को खोलने, बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल करने के साथ ही जिला प्रशासन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट–––

शासन ने पौड़ी जिले में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का अध्ययन करने के लिए भूतत्व और खनिकर्म विभाग के तीन अधिकारियों की एक टीम गठित की है। इस टीम में उप निदेशक/भूवैज्ञानिक डॉ. अमित गौरव, सहायक भूविज्ञानी कृष्ण सिंह सजवाण और तकनीकी सहायक रुचि गोदियाल शामिल हैं। यह टीम आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों की भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही भविष्य में आपदा से बचाव और सुरक्षा के सुझाव भी देगी।

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया प्रभावित परिवारों को मौके पर ही राहत राशि उपलब्ध करा दी गई है, साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है और खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई हैं। वहीं, विभागीय टीमें क्षतिग्रस्त बिजली और पानी की लाइनों की मरम्मत के साथ वैकल्पिक आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रही हैं।

मौसम

प्रदेश के अधिकांश जिलों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में भूस्खलन के चलते कई स्थानों पर अवरूद्ध सड़कों को खोलने का कार्य जारी है।

उधर, चमोली जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर अगले 5 दिनों तक जिले के सभी ट्रेकिंग मार्गों पर आवाजाही पर रोक लगा दी है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

इस बीच, मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, उधमसिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

निर्वाचन

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायतों में प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार नामांकन पत्र आज अपराह्न 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 3 बजकर 30 मिनट से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी 12 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। मतदान 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जिला पंचायत सभाकक्ष और संबंधित क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में संपन्न होगा। जिला और क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है।

भांग की खेती

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के उद्देश्य से पिछली सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी। इसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय को शून्य दशमलव तीन प्रतिशत से कम टेट्राहाइड्रो कैनिबिनोल– टी.एच.सी मात्रा वाली प्रजाति विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

पंतनगर विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉ. ए.एस. नैन ने बताया कि राज्य में भांग की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें टीएचसी मात्रा शून्य दशमलव तीन प्रतिशत से अधिक होती है, जबकि सरकार ने शून्य दशमलव तीन प्रतिशत से कम टीएचसी मात्रा वाली भांग की खेती को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने एक प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी है, जिसे राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया है।

विश्वविद्यालय ने बताया कि औद्योगिक भांग से कागज, बोर्ड, ईंट, फाइबर, इत्र, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा, तेल, ऑटोमोबाइल कलपुर्जे आदि सहित लगभग ढाई हजार प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। औद्योगिक भांग से बायोएथेनॉल तैयार करने की भी योजना है।